ISSN 2278-8808 SJIF 2014 = 4.889
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

रोजगार संवृद्धि की समस्या के सन्दर्भ में गाँधी जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

डॉ0 अनूप कुमार सिंह[1] & विवेक विश्वकर्मा[2]

[1] सहायक प्राध्यापक (असि0प्रो0), व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

[2] शोधार्थी, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के संकल्पनात्मक अथवा अवधारणात्मक विभेद के बावजूद दोनों का प्राथमिक उद्दे य एक अर्थव्यवस्था के नागरिकों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार एवम् वृद्धि करना है। इसी उद्दे य की प्रमुखता ने वि व पटल पर आर्थिक परिवे ा के अनुकूल विभिन्न आर्थिक प्रणालियों को जन्म दिया यथा पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। स्वतंत्रता के समय उपहार स्वरूप मिली ''**गतिहीन अर्थव्यवस्था**'' की ''**तीव्र संवृद्धि–प्राप्ति**'' उद्दे य हेतु मिश्रित आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत नियोजन को अपनाया गया। आयोजक यह मानते रहे कि उत्पादन और रोज़गार में सीधा धनात्मक सम्बन्ध है अर्थात् उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने से रोज़गार के स्तर में भी लगभग उसी अनुपात में वृद्धि होती है। इस कारण तीव्र संवृद्धि (सकल घेरलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि करके) द्वारा बेरोज़गारी को नियंत्रित किया जा सकता है। सम्भवतः यही कारण है कि ''**रोज़गार–युक्ति**'' बनाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन आँकड़ों से यह बात स्पश्ट होती है कि उत्पादन (जी0डी0पी0) और रोज़गार स्तर में कोई सीधा व धनात्मक सम्बन्ध नहीं ळें

रोज़गार तथा सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि

सारणी–1

(प्रतिशत में)

पंचवर्शीय योजनाएँ	**अवधि**	**सकल घरेलू उत्पाद में प्रति वर्श औसत वृद्धि दर**	**रोज़गार में वार्शिक औसत संवृद्धि दर**
पहली पंचवर्शीय योजना	1951–1956	3.6	0.39
दूसरी पंचवर्शीय योजना	1956–1961	4.2	0.85
तीसरी पंचवर्शीय योजना	1961–1966	2.8	2.83
तीन वार्शिक योजनाएँ	1966–1969	3.9	2.21
चौथी पंचवर्शीय योजना	1969–1974	3.3	1.99
पाँचवीं पंचवर्शीय योजना	1974–1979	4.8	1.84
वार्शिक योजनाएँ	1979–1980	(–) 5.2	–
छठी पंचवर्शीय योजना	1980–1985	5.7	1.73
सातवीं पंचवर्शीय योजना	1985–1990	5.8	1.89
दो वार्शिक योजनाएँ	1990–1992	3.4	1.5
आठवीं पंचवर्शीय योजना	1992–1997	6.6	2.6
नवीं पंचवर्शीय योजना	1997–2002	5.3	1.05
दसवीं पंचवर्शीय योजना	2002–2007	7.7	1.7
ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना	2007–2012	8.0	1.63
बारहवीं पंचवर्शीय योजना	2012–2017	9.5 (लक्ष्य)	2.4 (अनुमानित)

स्रोत : 1. आर्थिक समीक्षा 2011–12 तालिका ए–7

2. भारतीय अर्थव्यवस्था, डालचन्द्र बांगड़ी (अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली) पृ0 112।

3. दसवीं पंच वर्शीय योजना, खण्ड 1, तालिका 2.1 पृ0 26 और संलग्नक 5.14 पृ0 173,

टिप्पणी– पहली तीन योजनाओं के लिए विकास लक्ष्य राश्ट्रीय आय के सम्बन्धों में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना में यह निवल घरेलू उत्पाद था। इसके बाद सभी योजनाओं में वह कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद रहा है।

भारत में वर्श 1951 से 1956 के मध्य सारणी–1 के अनुसार जी0डी0पी0 की औसत वार्शिक वृद्धि दर 3.6 प्रति ात थी जो वर्श 1997 से 2000 के मध्य बढ़कर 6.1 प्रति ात और वर्श 2007 से 2012 के मध्य 8.0 प्रति ात हो गई। इसकी तुलना में उक्त समयावधि में रोज़गार में औसत वार्शिक वृद्धि दर क्रम ाः 0.39 प्रति ात से 0.98 प्रति ात और 1.63 प्रति ात रही। 1970 के द ाक के बाद रोज़गार की वार्शिक वृद्धि दर में लगातार गिरावट बनी रही, केवल आठवीं पंचवर्शीय योजना में थोड़ा सा सुधार दृश्टिगोचर होता है, जो बढ़कर 2.6 प्रति ात रही। दोनों की संवृद्धि दरों (जी0डी0पी0 और रोज़गार) में बढ़ता हुआ अन्तराल रोज़गारहीन संवृद्धि का सूचक है।

इस वर्तमान रोज़गारहीन संवृद्धि की समस्या के सन्दर्भ में गाँधी जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता दिखाई देती है। सन् 1947 में भारत सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की थी। इसे पहली पंचवर्शीय योजना में तीन अलग–अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया :– (1) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (2) अखिल भारतीय हस्त ाल्प बोर्ड (3) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। इसके अलावा तीन और बोर्ड स्थपित किए गए। ये बोर्ड थे :– (1) लघु उद्योग बोर्ड (2) नारियल जटा बोर्ड और (3) केन्द्रीय रे ाम बोर्ड। इस प्रकार पहली योजना की समाप्ति पर दे ा में छः बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे में **सभी लघु और कुटीर उद्योग** आते थे। कार्बे समिति (जिसे ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग की समिति भी कहा जाता है) ने 1955 में रोज़गार तथा समानता के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के महत्त्व पर बल दिया था। क्षेत्रीय समानता को प्राप्त करने हेतु इसने छोटे पैमाने के उद्योग के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार को सिफारि ा की थी क्योंकि ये उद्यम श्रम–गहन एवं रोज़गार–परक होते हैं। इस समिति की अनु ंसा भी गाँधी जी के आर्थिक विचारों से प्रेरित रही है। सरकार ने लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अगस्त 1991 में एक नई नीति की घोशणा की। इससे जहाँ पहले **उद्योग का अर्थ मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र माना जाता था, वहाँ इस नई नीति में इसके अन्तर्गत उद्योग से जुड़े सेवा व व्यावसायिक उद्योगों को भी भाामिल कर लिया गया**। इससे भारत में अब लघु उद्योग नीति की जगह लघु व्यवसाय नीति ने अपना स्थान ले लिया। गाँधी जी का **विकेन्द्रीकरण का आर्थिक विचार**, जिसके सन्दर्भ में उन्होंने कहा था कि यदि म ाीनों से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है और रोज़गार में भी वृद्धि होती है तो इस प्रकार का म ाीनीकरण समाज के लिए हितकारी है। गाँधी जी के इस आर्थिक विचार का व्यावहारिक रूपान्तरण कालान्तर में लघु एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित एक अन्य व्यापक एवं नवीनतम कदम अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 पारित कर उठाया गया। यह अधिनियम **'उद्यम'** की अवधारणा को वैधानिक जामा पहनाने का पहला प्रयास है तथा इसमें इन तीनों प्रकार के उद्यमों के एकीकरण की बात की गई। इसे अब समग्र रूप से एम0एस0एम0ई0 क्षेत्रक के रूप में जाना

जाता है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत और अपंजीकृत विनिर्माण तथा सेवा, दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। पंजीकृत एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र का आकार देखा जाये तो इसमें कार्यरत सभी इकाईयों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भाग वर्श 2009–10 में क्रम ाः 95.05 प्रति ात, 4.75 प्रति ात और 0.21 प्रति ात रहा। इस प्रकार गाँधी जी ने जिन लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात कही थी उनका सम्बन्ध पूर्णकालीन रोज़गार उपलब्ध कराने से था। इस एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम–2006 के पारित होने से वर्तमान और भविश्य में गाँधी जी के इस आर्थिक विचार को अधिक दृढ़ता प्राप्त होगी।

गाँधी जी राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। इस कारण उन्होंने हस्तकला कुटीर और लघु उद्योगों को स्थापित कर ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। इसके समर्थन में वे कहते हैं कि ''उत्पादन की पुरातन विधियों (श्रम–गहन उत्पादन तकनीक) का प्रयोग करना ही भारतीय आर्थिक–सामाजिक समस्याओं जैसे– बेरोज़गारी, निर्धनता और आर्थिक असमानता को दूर करने का एकमात्र विकल्प है, जिससे लाखों ग्रामीणों को रोज़गार मिल सके। उन्होंने म ीनों के प्रयोग की बढ़ती हुई लालसा का ज्यादा विरोध किया। वे श्रम की बचत करने वाली म ीनों का विरोध करते थे क्योंकि म ीनों के प्रयोग से होने वाले बेकार श्रमिकों के परिमाण में वृद्धि होती है, जो भूखों मरने की स्थिति में पहुँच जाते हैं।'' उनका विचार था कि ''म ीनों के प्रयोग से कुछ लोग लाखों लोगों का भोशण करते हैं, (यह केन्द्रीकरण को जन्म देता है) जिससे धन के केन्द्रीकरण (आर्थिक असमानता बढ़ती) तथा उससे सम्बन्धित बुराईयों को प्रोत्साहन मिलता है।'' उनका कहना था कि हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि भारत के ग्रामीणों के लिए कैसे फुर्सत का समय ढूँढ़ा जाये वरन् समस्या यह है कि कैसे उनके बेकार समय को उत्पादन हेतु सदुपयोग किया जाये। म ीनें हमें रोज़गार बढ़ाने की सुविधा में वंचित कर देती है। गाँधी जी इस तर्क से सहमत नहीं थे कि म ीनों से हमें सस्ती वस्तुएँ मिलती हैं। सूती वस्त्र उद्योग का उदाहरण देते हुए गाँधी जी ने कहा यदि इनसे हजारों श्रमिक बेकार हो जाते हैं, तो इन म ीनों का सूती वस्त्र वास्तव में खादी से महँगा है। वास्तव में गाँधी जी का म ीनों के सन्दर्भ में मानना है कि ''**कोई भी म ीन, जो मनुश्यों को श्रम के अवसरों से वंचित नहीं करती वरन् मनुश्यों को सहायता पहुँचा कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाती है और जिसका संचालन मनुश्य बिना उसका दास बने कर सकता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए**।''

इस प्रकार गाँधी जी आर्थिक विकेन्द्रीकरण के कट्टर समर्थक थे। वे चाहते थे कि उत्पत्ति का उद्देय उपभोग होना चाहिए (मानव के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के समर्थक) न कि बड़े–बड़े बाज़ारों का विस्तार। गाँधी जी ने आवयक वस्तुओं के सन्दर्भ में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उनका मत था कि हमें ऐसे गाँवों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो अपने उपभोग के लिए आवयक वस्तुओं का निर्माण कर सकें। हमारे समुदायों को दूसरों पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर होना चाहिए। गाँधी

जी उन समस्याओं से परिचित थे जिनका जन्म उत्पादन के केन्द्रीकरण द्वारा होता है और जिसके अन्तर्गत कुछ लोग उत्पत्ति को नियंत्रित कर (जैसाकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में होता) लाखों लोगों को अपना दास बना लेते हैं। अतः गाँधी जी का विचार था कि पुनर्गठन की कोई भी नीति उसी समय उचित कही जा सकती है जबकि उसका उद्दे य विकेन्द्रीकरण हो। आर्थिक भाक्ति का बड़े पैमाने पर केन्द्रीकरण न केवल आर्थिक दृश्टि से वरन् राजनीतिक दृश्टिकोण से भी खतरे से पूर्ण है। इस प्रकार गाँधी जी ने जहाँ राजनैतिक स्वतंत्रता को आधी–अधूरी स्वतंत्रता कहा, वहीं मात्र आर्थिक विकास को भी आधा–अधूरा विकास माना है। उनका कहना है कि धर्मविहीन राजनीति और नैतिकताविहीन विकास दोनों अर्थहीन हैं।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत गाँधी जी ने छोटे–छोटे उद्यमों की स्थापना पर बल दिया ताकि कच्चे माल को उसी स्थान पर निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सके। इससे ग्रामीणों को न केवल अपने उत्पादन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, वरन् वे अपने आसपास के समुदायों की सहायता भी कर सकेंगे। गाँधी जी की दृश्टि से यह न केवल तर्कपूर्ण एवम् व्यावहारिक है वरन् बहुत आव यक भी है। गाँधी जी के मत से सहमत होते हुए प्रो0 कोल कहते हैं कि ''**पूर्ण रोज़गार के लिए नियोजन हेतु यह आव यक होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों को विकेन्द्रित किया जा सके ताकि विस्तृत रूप से वैकल्पिक रोज़गार के साधन जुटाये जा सकें**।'' इसी उद्दे य से गाँधी जी ने ''**गाँवों की ओर वापसी**'' का नारा दिया। उनका कहना था कि बड़े पैमाने के केन्द्रित उद्योगों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों का जीवन गतिहीन हो जायेगा। गाँधी जी का वि वास था कि उत्पत्ति की विकेन्द्रित प्रणाली से लोगों को रोज़गार मिलने के साथ–साथ श्रमिकों की गति ीलता में वृद्धि होगी। विकेन्द्रित छोटे पैमाने के उद्यम सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक दृश्टिकोण से भी उचित है क्योंकि ये आर्थिक विपत्ति को दूर कर मानसिक तनाव को भी दूर करते हैं। गाँधी जी की नीति का समर्थन करते हुए डॉ0 ग्रेग (Dr. Gregg) का कथन है कि ''**गाँधी जी प्रत्येक किसान के लिए आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। प्रत्येक गांव के आर्थिक जीवन के लिए ''स्वायत्त नियंत्रण'' के समर्थक थे, एवम् जनसमूह द्वारा अनु ाासित ढंग से अहिंसा के माध्यम से उद्योगों एवम् राजनीति को नियंत्रित करना चाहते थे**।'' उनका यह भी मानना था कि ''**उत्पादन की केन्द्रीकरण की विधि ही असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है**।'' गाँधी जी के अनुसार वर्तमान आर्थिक बुराईयों को दूर करने के लिए यह आव यक है कि उपभोग और उत्पत्ति का स्थानीयकरण होना चाहिए ताकि अनाव यक रूप से उत्पत्ति को बढ़ाने की तीव्र इच्छा को रोका जा सके। अत्यधिक बढ़ता हुआ उत्पादन लाखों लोगों के जीवन स्तर को उठा नहीं सकता। गाँधी जी का कहना था कि जब तक बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ ही वितरण की समस्या नहीं सुलझाई जाती, तब तक बढ़ते हुए उत्पादन (बढ़ता हुआ जी0डी0पी0) का परिणाम दुखदायी ही होगा। गाँधी जी के विचारों से स्पश्ट होता है कि वितरण की समस्या बेरोज़गारी के साथ जुड़ी हुई है तथा केन्द्रित उत्पादन की विधि

ने बेरोज़गारी की समस्या खड़ी कर दी है। जैसाकि पा चात्य दे ों में औद्योगीकरण बढ़ने के साथ भी यह समस्या हल नहीं हो पायी है। इसे दूर करने के लिए गाँधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास का समर्थन किया। भारत के सन्दर्भ में गाँधी जी के विचारों की पुश्टि नियोजनकाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में बढ़ने वाले रोज़गारों से होती है।

एस.एस.आई./एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक में रोज़गार (लाख व्यक्ति)

वर्श	**एस.एस.आई. (लघु उद्यम)**	**एम.एस.एम.ई. (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)**
1984–85	90.00	315.00
1985–86	–	–
1986–87	–	–
1987–88	–	–
1988–89	–	–
1989–90	119.00	400.00
1990–91	124.30	437.80
1991–92	126.00	443.22[(1)]
1992–93	–	–
1993–94	–	–
1994–95	191.40	–
1995–96	197.93	–
1996–97	205.86	–
1997–98	213.16	449.70
1998–99	220.55	461.20
1999–00	229.10	473.00
2000–01	239.09	473.34
2001–02	249.09	483.50[(2)]
2002–03	260.21	–
2003–04	271.41	–
2004–05	282.57	–

2005–06	299.51	–
2006–07	312.52	805.23[3]
2007–08	322.28	842.00
2008–09	594.61	880.84
2009–10	626.34	921.79
2010–11	659.35	965.15
2011–12	695.98	1011.80
2012–13	699.23	1061.52
2013–14	–	1114.29 (अनुमानित)

स्रोत– 1. सातवीं पंचवर्शीय योजना खण्ड–।।, सारणी 4.2, पृ0 91–92

2. आठवीं पंचवर्शीय योजना खण्ड–।।, सारणी 6.1, 6.2, पृ0 164, 165, 166

3. वार्शिक रिपोर्ट एम.एस.एम.ई. 2013–14, सारणी 2.1, पृ0 15

भारत में कृशि के बाद रोज़गार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र लघु उद्योगों का ही है। 1994–95 में लघु क्षेत्र में 79.6 लाख इकाईयां थीं जो 2005–06 में 123.4 लाख इकाईयां (पंजीकृत + अपंजीकृत) थीं जिसमें क्रम ाः 191.40 लाख व्यक्ति और 299.21 लाख व्यक्ति रोज़गार में लगे हुए थे।

इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि वर्श 1972 से 1987–88 के मध्य समग्र औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि की दर 2.21 प्रति ात प्रतिवर्श थी, वहीं लघु क्षेत्र की इकाईयों में रोज़गार वृद्धि की दर 5.45 प्रति ात प्रतिवर्श थी। इस प्रकार सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों के सन्दर्भ (एम0एस0एम0ई) में रोज़गार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, जो वर्श 1984–85 में 315.00 लाख श्रमिक से बढ़कर वर्श 2013–14 में 1,114.29 लाख व्यक्ति हो गये। इस प्रकार इन क्षेत्रों में लगातार रोज़गार ही नहीं बढ़ा बल्कि रोज़गार की लोचता भी बनी हुई है।

जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का हिस्सा (प्रति ात में)

(2004–2005 की कीमतों के आधार पर)

वर्श	**जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक का हिस्सा** (प्रति ात में)		
	विनिमार्ण	**सेवा**	**कुल**
2006–07	7.73	27.40	35.13
2007–08	7.81	27.60	35.41
2008–09	7.52	28.60	36.12
2009–10	7.45	28.60	36.05

2010–11	7.39	29.30	36.69
2011–12	7.27	30.70	37.97
2012–13	7.04	30.50	37.54

स्रोत– फोर्थ ऑल इण्डिया सेंस्स ऑफ एम0एस0एम0ई 2006–07

एन0ए0एस0 (2013) सी0एस0ओ0

एन्वल सर्वे ऑफ इण्डस्ट्रीज – सी0एस0ओ0

जी0डी0पी0 में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र क्षेत्रक का हिस्सा (प्रति ात में)

वर्श

संवृद्धि दर मापन के लिए प्रयुक्त जी0डी0पी0 में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों सम्मिलित) के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का समग्र योगदान वर्श 2006–07 में 35.13% से बढ़कर वर्श 2012–13 में 37.54% हो गया। इसी समयावधि में कार्यरत उद्यमों की संख्या 361.76 लाख से बढ़कर 488.56 लाख हो गयी।

खादी और ग्रामीण उद्यम में रोज़गार की स्थिति

वर्श	**संचयी रोज़गार (प्रति लाख व्यक्ति)**	
	खादी	**ग्रामीण उद्योग**
2011–12	10.45	108.65
2012–13	10.71	114.05
2013–14	10.98	119.40
2014–15	10.69	132.72 (अनुमानित)

स्रोत– एन0ए0एस0 (2014) सी0एस0ओ0, एम0ओ0एस0पी0आई0

के.वी.आई. क्षेत्र द्वारा भी भारत में वर्श 2011–12 से वर्श 2014–15 के मध्य उपलब्ध कराये गये रोज़गार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जो क्रम ाः खादी में 10.45 लाख व्यक्ति से बढ़कर 10.69 लाख व्यक्ति और ग्रामीण उद्यमों 108.65 लाख व्यक्ति से बढ़कर 132.72 लाख व्यक्ति होने का अनुमान है।

भारत में खादी और ग्रामीण उद्यम तथा समग्र रूप में एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक का निश्पादन और रोज़गार की स्थिति तथा रोज़गार सम्भाव्यता गाँधी जी के उत्पादन संबंधी विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को दृढ़ता प्रदान करते हैं क्योंकि आज भी भारत की 65 प्रति ात जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और कृशि व उससे सम्बद्ध क्षेत्रों से उसका आर्थिक सहसम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में गाँधी जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता अधोलिखित रूप में परिलक्षित होती हैः–

1. भारत में अन्य बेरोज़गारी की तुलना में सबसे गम्भीर समस्या प्रच्छन्न बेरोज़गारी की है जिसका एकमात्र समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में एम0एस0एम0ई0 उद्यमों को स्थापित करना ही है।
2. बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु स्थापित उद्यमों में प्रति व्यक्ति रोज़गार के अवसर सृजन करने में लगने वाली प्रति व्यक्ति पूँजी से एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में 7 से 8 व्यक्तियों के लिए रोज़गार का सृजन किया जा सकता है।
3. एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोज़गार की लोच और रोज़गार सम्भावना कम है। इस कारण इस क्षेत्र में अधिक रोज़गार सृजन की सम्भावना विद्यमान है।
4. भाहरीकरण के कारण श्रम भाक्ति का गाँवों से भाहरों की स्थानान्तरण एवं रोज़गार उपलब्ध न हो पाने के कारण उत्पन्न भाहरी निर्धनता की समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
5. एम0एस0एम0ई0 उद्यमों में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। अन्तर्क्षेत्रीय समानता के सन्दर्भ में समानतापरक होते हैं।
6. एम0एस0एम0ई0 अंतर–वैयक्तिक समानता के सन्दर्भ में साम्या–परक होते हैं अर्थात् केवल अल्प निवे ा की जरूरत होती है। इन उद्यमों में न्यूनतम प्रति इकाई निवे ा के फलस्वरूप रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इस कारण साम्यता को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
7. एम0एस0एम0ई0 का सम्बन्ध मुख्यता आव यकता की वांछनीयता से है जो मानव कल्याण को बढ़ाने में सहायक होती है। इसी को गाँधी जी ने अन्य भाब्दों में कहा है कि जीवन स्तर से (Standard of Living) से पहले जीवन मान (Standard of Life) को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

देसाई ए0आर0, रूरल डेवलपमेण्ट एण्ड ह्यूमन राईट्स, इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकली वीकली, 1/8/87

कुमारप्पा, इकॉनामी आफ परमासेन्स, सर्वसेवा संघ प्रका ान, वाराणसी, पृ0 149–157।

सिंगय चरण, ''गाँधीयन सल्यु ान टू इकनॉमी प्राब्लम'', इलस्ट्रेटेड वीकली, अक्टूबर 2, 1997

उपाध्याय, निर्मलाय? ''महात्मा गाँधी की स्वराज विशयक धारणा'' लोकतन्त्र समीक्षा जुलाई दिसम्बर 1982, अंक 3–4, पृश्ठ 311–314

सातवीं पंचवर्शीय योजना खण्ड ।।, सारणी 4.2, पृ0 91 से 92

आठवीं पंचवर्शीय योजना खण्ड–2, सारणी 6.1, 6.2, पृ0 164 से 166

वार्शिक रिपोर्ट एम.एस.एम.ई., 2013–14, सारणी 2.1, पृ0 15

आर्थिक समीक्षा 2007–08

आर्थिक समीक्षा 2009–10